

**वित्त मंत्रालय**  
**लोक उद्यम विभाग**  
**मंत्रिमंडल के लिए नवंबर, 2021 माह हेतु मासिक सारांश**

नवंबर, 2021 माह के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां और महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में एक अद्यतन रिपोर्ट (अपडेट) निम्नवत है:-

**1. कैपेक्स लक्ष्य:**

नवंबर, 2021 तक के चुनिंदा सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में 5.95 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य और उसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी 6 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 5.95 लाख करोड़ रुपये (लगभग) के अनुमानित वार्षिक व्यय के मुकाबले, उपलब्धि 3.07 लाख करोड़ रुपये (लगभग) या लगभग 51.74% है। रेलवे बोर्ड के संबंध में सूचना अक्टूबर, 2021 तक है।

**2. सीसीईए नोट्स:**

अन्य मंत्रालयों/विभागों के 3 सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट्स के मसौदा की डीपीई द्वारा जांच की गई और उस पर टिप्पणियां जारी की गईं।

**3. समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क:**

इस माह के दौरान 38 सीपीएसईज़ के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए एमओयू मूल्यांकन पर आईएमसी की बैठकों का आयोजन किया गया था और मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया गया था।

**4. सीपीएसईज़ का कॉर्पोरेट गवर्नेंस:**

i) डीपीई ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में बोर्ड स्तर के पदों से नीचे के 55 पदों को दिनांक 18.11.2021 के आगे 3 साल की अवधि के लिए तत्काल समावेश के नियम से छूट देने पर सहमति व्यक्त की।

ii) डीपीई ने लोक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के पद को आईटीडीसी लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष और आईटीडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अलग से विभाजित करने के पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया और इस पर सहमति जताई।

**5. जीईएम और एमएसएमई के माध्यम से खरीद से संबंधित मामले:**

i) सभी सीपीएसईज़ से अनुरोध किया गया था कि वे पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिन्हित पांच स्थलों अर्थात् वाराणसी, आगरा, खजुराहो, हम्पी और बोधगया में ऑफ सीजन (अप्रैल से सितंबर) के दौरान अपनी बैठकों/सम्मेलनों/सेमिनारों/प्रदर्शनियों का कार्यक्रम तैयार करें।

ii) वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, सभी सीपीएसईज़ से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए ई-रुपये यूपीआई वाउचर को व्यापक रूप से अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

iii) व्यय विभाग के (i) खरीद और परियोजना प्रबंधन और (ii) फर्मों को बोली से रोकने संबंधी अनुदेश, सूचना और अनुपालन के लिए सीपीएसईज़ को भेज दिए गए थे।

iv) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार सभी सीपीएसईज़ को आउटरीच और संचार ब्यूरो के माध्यम से प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, आउटडोर और अन्य मीडिया में अपने विज्ञापन जारी करने के लिए सूचित किया गया था।

6. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और विशेष अभियान:

i) माह के दौरान छः आईएमजी/सीजीडी/सीएमडीसी बैठकें आयोजित की गईं।

ii) अपर सचिव, डीपीई की अध्यक्षता में दिनांक 12 नवंबर, 2021 को वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत 3 बंद होने वाले सीपीएसईज़ के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं:

i) डीपीई ने सीपीएसईज़ के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे (i) सीपीएसईज़ द्वारा भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के लिए नियामक ढांचा / दिशानिर्देश और इसकी चुनौतियां, (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के माध्यम से, मानव संसाधन से संबंधित मुद्दे जैसे आरटीआई अधिनियम, स्थापना नियम, एफआर (56)जे के तहत समीक्षा, जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही, मतर्कता आदि (iii) आईआईएम, रोहतक के माध्यम से साइबर सुरक्षा, और (iv) सीपीएसईज़/एसएलपीई के अधिकारियों के लाभ के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से सीपीएसईज़ में महिला सशक्तिकरण पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से दो प्रशिक्षण कार्यक्रम और दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

ii) डीपीई ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से गुवाहाटी में दिनांक 24 नवंबर, 2021 को सीपीएसईज़ के सीएसआर प्रमुखों की इंटरैक्टिव कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विभिन्न सीपीएसईज़ के 80 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

8. अन्य घटनाएं:

"आजादी का अमृत महोत्सव" के रूप में संविधान दिवस समारोह

हमारे संविधान को अपनाने के 75 वर्ष के अवसर पर प्रस्तावना पठन और एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन "आजादी का अमृत महोत्सव" के रूप में किया गया। सचिव (पीई) की अध्यक्षता में डीपीई के अधिकारियों ने, संसद के केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, दिनांक 26.11.2021 को प्रस्तावना का पठन किया। डीपीई के कुल 70 अधिकारियों ने ऑनलाइन प्रस्तावना रीडिंग में भाग लिया है और प्रमाण पत्र डाउनलोड किए हैं। डीपीई के 31 अधिकारियों ने संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज में भाग लिया और प्रमाण पत्र डाउनलोड किए।

\*\*\*\*\*